www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 344 | जौनपुर, मंगलवार, 04 अगस्त 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

निरंतर प्रयास और साधना से हमारी प्रतिभा और निखरती है - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सुभाषित शेयर किया है। पीएम मोदी की ओर से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा गया, "निरंतर प्रयास और साधना से हमारी प्रतिभा और निखरती है। आज हमारे युवा इन्हीं गुणों को आत्मसात कर दुनियाभर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं।" इसके साथ ही उन्होंने एक संस्कृत श्लोक, "न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धरू कालेनात्मनि विन्दतिध" साझा किया। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। कर्मयोग या साधना के द्वारा

जिसका अंतःकरण भली–भांति शुद्ध हो गया है, वह साधक समय आने पर उस परम ज्ञान को अपने आप ही अपने भीतर आत्मा में अनुभव कर लेता है।" बीते दिन सोमवार को पीएम मोदी ने श्लोक शेयर करते हुए लिखा था, "त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि दैवे धैर्यात्कदाचित्स्थितिमाप्नुयात्सः। याते समुद्रेऽपि च पोतभङ्गे सांयात्रिको वाञ्छति कर्म एव।" जिसका हिंदी अर्थ है कि भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य के कारण वह कभी भी अपनी खोई हुई अनुकूल स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार समुद्र के बीच में जहाज टूट जाने पर भी एक कुशल नाविक केवल अपने कर्म, अर्थात जीवित रहने और तैरने के प्रयास की ही इच्छा करता है और हिम्मत नहीं हारता। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई को सुभाषित शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, "गुरु पूर्णिमा की सभी देशवासियों को बहुत–बहुत बधाई। गुरु ज्ञान के साथ ही अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर उन्हें सुविचार और सुसंस्कारों से सुशिक्षित करते हैं। आइए, उनके आदर्शों को अपने जीवन का संबल बनाएं।"

यूपी विधानसभा में 59 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट, केंद्र से मिलेगी 11 हजार करोड़ की सहायता

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे बीच वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए अनुपूरक बजट में पेश किया। उन्होंने कुल 59,019.54 करोड़ रुपये की अनुपूरक बजट मांग (अतिरिक्त बजट) पेश किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240.97 करोड़ की मदद अंशदान (हिस्सेदारी) के रूप में मिलेगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बार –बार विपक्षी सदस्यों को अपनी सीट पर बैठने और चर्चा में भाग लेने का आग्रह करते रहे, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी जारी रखी। इस बीच जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खडेध हुए तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और तेज कर दिया। विपक्षी सदस्य नारे लगा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष न तो सदन की मर्यादा का ख्याल रखता है और संवैधानिक मूल्यों का ही पालन कर रहा है। आज सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए राज्य सरकार ने कुल 59,019.54 करोड़ रुपये की अनुपूरक बजट मांग (अतिरिक्त बजट) पेश किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240.97 करोड़ की मदद अंशदान (हिस्सेदारी) के रूप में मिलेगी। केंद्र से मिलने वाली राशि को घटाने के बाद राज्य सरकार के खजाने (समेकित निधि) पर 47,778.57 करोड़ रुपये का शुद्ध वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस खर्च का इंतजाम सरकार टैक्स (कर) और गैर–टैक्स (करेतर) से होने वाली अपनी राजस्व आय के तय लक्ष्यों को पूरा करके तथा फालतू (अनुत्पादक) खर्चों में कटौती करके करेगी।

संक्षिप्त खबरें

पंजाब सरकार का कर्मचारियों के प्रति विरोधी रवैया सामने आया है– अकाली दल

चंडीगढ़, (एजेंसी)। शिरोमणि अकाली दल (सिअद) ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों से पार्टी का समर्थन करने की अपील की। पार्टी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश का भी स्वागत किया, जिसमें पंजाब सरकार को 15 दिनों के भीतर 14,191 करोड़ रुपए का महंगाई भत्ता (डीए) बकाया चुकाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी न किसी बहाने से कर्मचारियों को डीए का लाभ न देने की पूरी कोशिश की। उसने वरिष्ठ नेताओं हरपाल चीमा, अमन अरोड़ा और बलजीत कौर की तीन सदस्यीय समिति बनाई, जिसने सिफारिश की कि राज्य के कर्मचारियों को अतिरिक्त डीए लाभ देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके लाभ केंद्र के बराबर या उससे भी बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि समिति ने इस तथ्य का भी हवाला दिया कि राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है और यह भी कहा कि वह डीए संशोधन के मामले में केंद्र सरकार का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है।यह कहते हुए कि ये सभी तथ्य कोर्ट के रिकॉर्ड में हैं, मजीठिया ने कहा कि सरकार जनता के सामने एक बात कह रही है और कोर्ट में दूसरी। उन्होंने कहा कि श्गुरु द्रोहीश मुख्यमंत्री भगवंत मान दावा करते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार अदालत में इसके उलट बात कह रही है। इसी तरह, विकास को लेकर आप सरकार का किया गया ।

विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता चल रहा है और आज यानी मंगलवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज रहने की उम्मीद है। दोनों खेमों ने अपनी–अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जिससे कार्यवाही में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए एकजुट दिखाई दे रहा है।सुबह 10रू30 बजे विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका मुख्य मुद्दा 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के दान चंदे में कथित गड़बड़ी के आरोप हैं। विपक्ष इन मामलों पर गृह मंत्री से जवाब चाहता है।दूसरी ओर, सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का सामना करने की योजना बना ली है। हंगामे के बावजूद सरकार का ध्यान विधायी कामकाज और वित्तीय कार्यों को आगे बढ़ाने पर है। जरूरी विधेयकों को पारित कराने की कोशिश की जाएगी। एनडीए की बैठक सत्ता पक्ष आज संसद पुस्तकालय भवन में अपनी साप्ताहिक श्मंगलवार मिलनश बैठक करेगा। इसमें विपक्षी विरोध से निपटने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रखने पर चर्चा होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का पूर्वोत्तर दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की करेंगे समीक्षा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 4 से 6 अगस्त तक पूर्वोत्तर भारत के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लेंगे। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 4 अगस्त को नई दिल्ली से असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे और रात वहीं प्रवास करेंगे। दौरे के दूसरे दिन, 5 अगस्त को वे असम के चराइदेव जिले का दौरा करेंगे, जो हाल की बाढ़ के दौरान सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल रहा है। यहां वे स्वास्थ्य सुविधाओं, राहत कार्यों और प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे नागालैंड के मोन जिले के लिए रवाना होंगे, जहां विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेंगे। नागालैंड के दौरे के बाद नड्डा उसी दिन डिब्रूगढ़ लौटेंगे। यहां वे असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, चिकित्सा ढांचे की बहाली, राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।

बांकीपुर में हार के बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से की मुलाकात

बिहार, (एजेंसी)। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार ने मंगलवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिससे बिहार में के भविष्य को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गईं। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यह बैठक बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के हाथों भाजपा को मिली चौंकाने वाली हार के ठीक बाद हुई है। इस उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों से हराया, जिससे बीजेपी को अपने सबसे मजबूत चुनावी गढ़ों में से एक में बड़ा झटका लगा। बांकीपुर विधानसभा सीट 1995 से लगातार भाजपा के पास रही थी। इस सीट का प्रतिनिधित्व कई सालों तक स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने किया था, जिसके बाद उनके बेटे नितिन नवीन ने इसे संभाला और 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के सीट छोड़ने पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी। हालाँकि, भाजपा इस सीट को बचाने में नाकाम रही और प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी डेब्यू में ही निर्णायक जीत हासिल की। यह नतीजा इसलिए भी खास था क्योंकि जन सुराज पार्टी नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, इसलिए भाजपा के गढ़ में उसकी जीत एक बड़ी राजनीतिक कामयाबी मानी जा रही है। इस नतीजे ने बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा को और तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ उपचुनाव में उलटफेर से कहीं ज़्यादा अहम मान रहे हैं। बीजेपी के लंबे समय से गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर मिली हार को कई लोग अगले विधानसभा चुनावों से पहले वोटरों की बदलती पसंद का संकेत मान रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान, कई सालों तक चुनावी रणनीतिकार रहने के बाद प्रशांत किशोर ने खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक नेता के तौर पर पेश किया।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा का हंगामा

लखनऊ, (संवाददाता)। चार अगस्त उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के सदस्यों ने सदन में हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बार–बार अनुरोध के बाद भी सदस्यों के हंगामा जारी रखने पर कार्यवाही को दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। सत्र की शुरुआत होते ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सदन की सारी कार्यवाही रोककर राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा कराने की मांग की। इसके बाद सपा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समक्ष पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्य ''चंदा चोर कहां मिलेंगे–भाजपा के दफ्तर में'' जैसे नारे लगा रहे थे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि यह मामला न तो तात्कालिक है और न ही ऐसी कोई स्थिति है, जिसके कारण सदन की कार्यवाही रोकने की आवश्यकता हो। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज आस्था और भगवान राम की बात कर रहे हैं, उन्होंने 1990 में रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं और राम मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी की थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण रुकवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में कई अधिवक्ताओं को भी खड़ा किया गया था। खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के कथित चढ़ावा विवाद की जांच जारी है और मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं कराई जा सकती। इस दौरान सपा सदस्यों ने ''चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी'' के मुद्दे पर नारेबाजी और तेज कर दी। अध्यक्ष महाना ने कहा, ''जिन लोगों ने चंदा दिया, वे उसकी रसीद लेकर आ जाएं। धार्मिक आस्था पर चोट करना उचित नहीं है।'' उन्होंने सपा के शाहिद मंजूर और जाहिद बेग सहित अन्य सदस्यों का नाम लेते हुए ।

कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में थी, चढ़ावा विवाद पर रिजिजू का बड़ा बयान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मंगलवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष ने मंगलवार राम मंदिर के चढ़ावे और प्रबंधन में अपारदर्शिता तथा गंभीर अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राम मंदिर ट्रस्ट और उसमें मिले बहुमूल्य उपहारों, नकद दान, जमीन की खरीद तथा उसके प्रबंधन को लेकर उठे गंभीर आरोपों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस व उसके सहयोगियों ने पूर्व में भगवान राम को लेकर जो बयान दिए थे, उन पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह सदन केवल नेता प्रतिपक्ष का नहीं। उन्हें इस तरह बार–बार बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस बीच सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी अपनी सीटों से उठकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने लगे। वहीं विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे जिस को देखते हुए सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की करवाई को स्थगित कर दिया। इस हंगामे से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखते हुए कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं सदन में ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी। भूमि पूजन से लेकर रामलला की प्राण–प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित रहे।

बांकीपुर उपचुनाव परिणाम को प्रशांत किशोर ने बताया बिहार की आवाज

पटना, (एजेंसी)। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत को केवल एक विधानसभा सीट का परिणाम मानने से इनकार किया है। मतगणना केंद्र के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह परिणाम बिहार की जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों का संदेश है, जिसे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव परिणाम का असली मुद्दा बिहार का विकास, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसर और युवाओं का पलायन रोकना होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बिहार के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।बौ चुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में जीत का श्रेय लेने के बजाय बिहार के भविष्य और जनता की समस्याओं को केंद्र में रखा। उन्होंने समर्थकों का आभार जताया और कहा कि लोकतंत्र में हर मत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जन सुराज के पक्ष में मतदान किया, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही उन्होंने उन मतदाताओं का भी सम्मान किया, जिन्होंने अन्य उम्मीदवारों को वोट दिया। उनके अनुसार, चुनावी मतभेद के बावजूद क्षेत्र का हर नागरिक सम्मानित है और सभी के हित में काम करना जरूरी है।जन सुराज प्रमुख ने कहा कि बिहार के युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, ताकि उन्हें मजबूरी में दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है,।

जनता ने भाजपा सरकार को सिखाया सबक, कुशासन से है गुस्सा – तेजस्वी यादव

बिहार, (एजेंसी)। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जनता का सीधा फैसला बताया और कहा कि यह नतीजा राज्य के कामकाज से जनता की बढ़ती नाराजगी का नतीजा है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे जनता का सीधा फैसला हैं दृ यह बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री के खध्लिाफ जनता के गुस्से का नतीजा है। सिर्फ 100 से 150 दिनों के अंदर बीजेपी दो बड़े चुनाव हार चुकी है, जिससे साबित होता है कि सम्राट चौधरी जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहे हैं। विकास पर ध्यान देने के बजाय, सरकार ने नकारात्मक राजनीति, नाम बदलने और विपक्ष को परेशान करने को प्राथमिकता दी है, और इसीलिए वोटरों ने उन्हें सबक सिखाया है। उन्होंने बिहार के दो सीनियर अधिकारियों की मौत की पुलिस जांच की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और पीड़ित परिवार का सही आरोप है कि मुख्य आरोपी, जिसमें सोनू सिंह भी शामिल हैं, को बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही हत्या की थ्योरी को कैसे अंतिम रूप दे सकती है? वे दावा कर रहे हैं कि ड्राइवर ने काम के दबाव में ऐसा किया, जबकि उसने बार–बार अपना बयान बदला है और उसकी पत्नी का कहना है कि उस पर दबाव डाला गया था। इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए यादव ने राज्य सरकार पर कानून–व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में दो बड़े अधिकारियों की हत्या हो चुकी है, फिर भी सरकार और प्रशासन चुप हैं और प्रभावशाली लोगों व अपराधियों को बचा रहे हैं। राज्य के अधिकारी एक भ्रष्ट सिस्टम के तहत डर के माहौल में काम कर रहे हैं, जहाँ शरिश्वत दो और पोस्टिंग पाओश का खेल चलता है ।

संपादकीय

लोकतांत्रिक पहल का नया दरवाजा खुला

अवसरहीनता से जूझ रही नई पीढ़ी श्अतीत के गौरव की वापसी्य, श्विकसित भारतत्य, या श्विश्व गुरुत्य जैसी कहानियों से प्रभावित नहीं है। वह मोदी सरकार से उसके 12 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। एक मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर करने की कॉकरोच आंदोलन की सफलता से जनमत के एक हिस्से में ष्लोकतंत्र के जिंदा होनेष का बना अहसास यही बताता है कि हालिया वर्षों में ष्लोकतंत्र की स्थितिष लेकर इस दायरे में कितनी मायूसी छायी रही है। यह भावना जवाबदेही तय करने वाली संस्थाओं के पंगु होने और लोकतांत्रिक अधिकारों के सिकुड़ते जाने की धारणा से पैदा हुई है। कॉकरोच आंदोलन दरअसल, इन सबसे ही गहराती हताशा एवं बढ़ते आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति का जरिया बना। इस दौरान दिखी खासकर युवा वर्ग की उत्साही भागीदारी एवं जोश भरी प्रतिक्रियाओं ने कुछ ठोस संकेत दिए। मसलन, यह कि हवाई कथानकों के जरिए जमीनी नाकामियों को छिपाने में सत्ता पक्ष को मिली कामयाबियों का दौर अब ठहर चुका है। अवसरहीनता और अंधकारमय भविष्य से जूझ रही नई पीढ़ी श्अतीत के गौरव की वापसी्य, श्विकसित भारतत्य, या श्विश्व गुरुत्य जैसी कहानियों से प्रभावित नहीं है। वह नरेंद्र मोदी सरकार से उसके 12 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि नैरेटिव कंट्रोल की मोदी की क्षमता पहली बार चूकती नजर आई। मध्य एवं उच्च मध्यम वर्ग से आए पढ़े–लिखे एवं नई संचार तकनीक के इस्तेमाल में माहिर नौजवानों ने जो किताबों में पढ़ा और सरकारी प्रचार–तंत्र से सुना, उसका परीक्षण वे हकीकत के बरक्स कर रहे हैं। इससे लोकतांत्रिक पहल का नया दरवाजा खुला है। लेकिन हमें सचेत रहना चाहिए कि अक्सर स्वतरूस्फूर्त, असंगठित, एवं नेतृत्व–विहीन आंदोलन ऐसा अवसर पैदा करने के बाद बिखराव का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अवसरों का लाभ उठाने का दायित्व संगठित राजनीतिक दलों पर होता है। फिलहाल, इस बिंदु पर आशाजनक संकेत नहीं हैं। इसलिए कि नई पीढ़ी के आंदोलन से उपजी संभावना को उम्मीद जगाने वाले जिस एजेंडे से राजनीतिक पूंजी में तब्दील किया जा सकता है, भाजपा विरोधी दलों में वैसा करने की क्षमता या जज्बे का अभाव नजर आता है। अतरू इस आंदोलन से मोदी की आभा भले धुंधली हो गई हो, लेकिन संभव है कि सत्ता तंत्र पर उनकी पकड़ कमजोर करने का रास्ता अभी भी दुरूह बना हुआ हो।

विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से क्यों रोका जाए

सुदर्शन आयंगारशिक्षा

बार–बार होने वाले राष्ट्रीय परीक्षा–संकट अत्यधिक केंद्रीकरण पर भी पुनर्विचार की मांग करते हैं। जब एक ही व्यवस्था करोड़ों युवाओं के भविष्य को नियंत्रित करती है तब एक प्रशासनिक गलती पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर सकती है। गांधीजी का विश्वास विकेंद्रीकरण, स्थानीय जिम्मेदारी और लोगों के निकट निर्णय लेने में था। शिक्षा में भी विविधता, संस्थागत स्वायत्तता और स्थानीय जवाबदेही आवश्यक हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) ने प्रेस विज्ञप्ति में विद्यार्थियों से कहा है कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें और परीक्षा–व्यवस्था के विरुद्ध चल रहे विरोध–प्रदर्शनों से दूर रहें। पहली नजर में यह सलाह बिल्कुल उचित लगती है। विद्यार्थी पढ़ेंगे नहीं, परीक्षाओं की तैयारी नहीं करेंगे तो उनका भविष्य कैसे बनेगा? सवाल यह है कि क्या पढ़ाई और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना एक–दूसरे के विरोधी हैं? क्या एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हुए अपनी परीक्षा–व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा सकता? क्या डिग्री हासिल करने की चिंता उसे अपने भविष्य से जुड़े अन्याय के प्रति चुप रहने के लिए बाध्य कर देती है? यहीं से शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य का प्रश्न सामने आता है। क्या शिक्षा केवल कक्षाओं में उपस्थित होने, परीक्षाएं देने और डिग्रियां प्राप्त करने का नाम है? या शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना भी है जो सत्य और असत्य में अंतर कर सकें, अन्याय को पहचान सकें और उसके विरुद्ध खड़े होने का साहस रख सकें? मानकीकृत और प्रवेश परीक्षाएं महात्मा गांधी के लिए शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन नहीं थी। शिक्षा का संबंध चरित्र, विवेक, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी से था। उनके लिए शिक्षित व्यक्ति वह नहीं था जो केवल बहुत कुछ जानता हो बल्कि वह था जो सत्य के पक्ष में खड़े होने और अन्याय का प्रतिरोध करने का नैतिक साहस रखता हो। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं। 1920 में गांधीजी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना केवल एक और विश्वविद्यालय बनाने के लिए नहीं की थी। वह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध स्वराज्य के व्यापक संघर्ष का हिस्सा था। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के दौरान शिक्षण संस्थानों से यह नहीं कहा गया कि वे देश में हो रहे संघर्ष से अलग रहें और विद्यार्थियों का एकमात्र कर्तव्य कक्षाओं और परीक्षाओं तक सीमित है। दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में भी शिक्षा को सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी से अलग नहीं किया गया। प्रश्न यह था, कि क्या शिक्षा आज्ञाकारी प्रजा बनाएगी या जिम्मेदार नागरिक? विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने वाली संस्थाएं नहीं हैं। वे समाज की नैतिक चेतना के निर्माण की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर विरोध उचित है या विद्यार्थियों को हर मुद्दे पर सड़कों पर उतर जाना चाहिए। विरोध कोई फैशन नहीं है और न ही स्वयं में कोई लक्ष्य। विद्यार्थियों को हिंसा, उन्माद और भीड़तंत्र से दूर रहना चाहिए। किसी आंदोलन का मूल्य इस बात से तय होता है कि वह किस उद्देश्य के लिए है, उसकी पद्धति क्या है और वह किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहता है। दुष्यंत के इस शेर को न भुला देंरू श्सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।्य 1974–75 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हमारा प्रयास यही था कि व्यवस्था में परिवर्तन की मांग को नैतिकता, अनुशासन और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से जोड़ा जाए। कॉलेज और विश्वविद्यालय आज विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा–व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे प्रश्नों को केवल श्पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाला मुद्दा्य कहना वास्तविकता से आंखें मूंदना है। परीक्षा की विश्वसनीयता सीधे विद्यार्थी के भविष्य से जुड़ी है। प्रश्नपत्र लीक हों, परीक्षाओं में अनियमितताएं हों, प्रशासनिक लापरवाही हो या अलग–अलग विद्यार्थियों के साथ असमान व्यवहार किया जाए, तो इसका प्रभाव केवल किसी एक छात्र पर नहीं पड़ता। लाखों युवाओं के जीवन, समय, धन और भविष्य पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए प्रश्न उठाना विद्यार्थियों का अधिकार ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी है। (एआईयू) ने विद्यार्थियों को अफवाहों और अटकलों से सावधान किया है। यह सलाह उचित है। लोकतांत्रिक समाज में अफवाहें निर्णय का आधार नहीं बन सकतीं लेकिन लोकतंत्र में सरकारी आश्वासन भी अपने आप में पर्याप्त नहीं होते। विश्वास पारदर्शिता से पैदा होता है, स्वतंत्र जांच से मजबूत होता है और जवाबदेही से कायम रहता है। नीट यूजी परीक्षा से जुड़े 2024 के विवादों ने देश में परीक्षा–व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए। यदि किसी व्यक्ति पर किसी मामले में कथित रूप से मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगे और बाद में जांच एजेंसी यह कहे ।

आखिर नहीं कर पाते शिक्षा मंत्री अपना कार्यकाल

योगेंद्र

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और सरकार की प्राथमिकताओं पर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ इस्तीफा देने वाले शिक्षा मंत्री ध र्मेन्द्र प्रधान पर नहीं, बल्कि मोदी सरकार के दौरान शिक्षा मंत्रालय की पूरी दिशा को लेकर भी उठ रहे हैं। साल 2014 से केंद्र में सत्ता में आने के बाद से अब तक मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल श्निशंकश और धर्मेंद्र प्रधान को अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। पांचवा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है, हालांकि जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मोदी सरकार को तय करना है कि जोशी ही पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री रहेंगे या किसी नए चेहरे की तलाश करके उसको स्वतंत्र रूप से शिक्षा मंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जोशी भी विवादों में रहे हैं। साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो गैंग रेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कध्ैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई पर जब चौतरफा सवाल उठ रहे थे, तब प्रल्हाद जोशी ने इसका बचाव किया था। सवाल यही है कि आखिरकार कोई भी शिक्षा मंत्री अपना कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर पाया। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय ही ऐसा प्रमुख मंत्रालय रहा, जिसकी कमान पांच अलग–अलग मंत्रियों ने संभाली वहीं, गृह, विदेश, वित्त, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे मंत्रालयों में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रही। शिक्षा, संस्कृति और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आईएनबी) ऐसे कुछ चुनिंदा मंत्रालय हैं, जिन्हें सॉफ्ट पावर की तरह देखा जाता है और जो संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अहम रहे हैं। यही कारण है कि यहां विवाद ज्यादा हुए और अस्थिरता भी उतनी ही दिखती है। गौरतलब है कि आईएनबी में 12 साल के भीतर सात केंद्रीय मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में पांच केंद्रीय मंत्री बने हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने मानव संसाध ान विकास मंत्रालय संभाला मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह जिम्मेदारी रमेश पोखरियाल श्निशंकश को मिली। मगर 2021 में हुए कैबिनेट विस्तार के दौरान धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर एक महीने तक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जंतर–मंतर पर बैठे रहे और आखध्रिकार केंद्र सरकार दबाव में आई और प्रधान को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। नीट परीक्षा के लीक होने का मामला अलग कर दें, तो संघ से जुड़े उन सभी प्रमुख लक्ष्यों को धर्मेंद्र प्रधान बिना शोर–शराबा किए लागू करा पाने में सफल रहे हैं, जिनकी कोशिश उनके पूर्ववर्तियों ने जोर लगाते हुए की और विवादों में फंसते गए। गौरतलब है कि 2014 में बनी पहली मोदी कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रध ाान को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया, फिर मोदी के दूसरे कार्यकाल में वे शिक्षा मंत्री बने और मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी यह जिम्मेदारी जारी रही। प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को बढ़ावा मिला। मातृभाषा और कई भाषाओं में शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। मगर तीन–भाषा फॉर्मूला पर तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ लंबे समय तक वे विवाद के केंद्र में भी रहे। विरोधियों ने उन पर राजनीतिक हस्तक्षेप और हिंदी थोपने का आरोप लगाया, जिससे शिक्षा नीति केंद्र बनाम राज्य के विवाद का मुद्दा बन गई। मोदी सरकार के कार्यकाल के चारों शिक्षा मंत्रियों में से एक भी अपना विजन लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। रणनीतियां ऊपर से बनती थीं। ये जरूर है कि हर मंत्री का उसे लागू करने का तरीकध अलग हो सकता है जैसे, स्मृति ईरानी ज्यादा मुखध्र थीं, जावड़ेकर रणनीतिक चुप्पी वाले व्यक्ति थे। मोदी के शासन में शिक्षा विभाग में जो भी नीतियां अपनाई गईं, वे सभी वाम विचारधारा को हटाने के मकध्सद से लागू हुईं। संघ का मकध्सद भारत की शिक्षा व्यवस्था से वाम विचारधारा वाली शिक्षा–पद्धति को हटाना है, क्योंकि संघ मानता है कि वे मुगलों के समर्थक रहे हैं। संघ की नजर में, मुगल घुसपैठिए हैं और देश की मुस्लिम आबादी उनकी वंशज है। संघ पर आरोप लगते रहें कि इस एजेंडे को पूरा मोदी सरकार के जरिए कराया जा रहा है। इसी लक्ष्य को साध ाने के लिए मोदी सरकार के चार शिक्षा मंत्रियों के चयन का पैमाना रहा है। ष्मृति ईरानी को छोड़ दें, तो नवनियुक्त शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल श्निशंकश और धर्मेंद्र प्रधान संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वाजपेयी के जमाने में भी संघ से आने वाले मुरली मनोहर जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जो दर्शाता है कि संघ इस मंत्रालय में अपना दखध्ल हमेशा चाहता रहा है। स्मृति ईरानी के साथ उनके नाम पर डिग्री विवाद, जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला की आत्महत्या जैसे विवाद जुड़ चुके थे। स्मृति ईरानी संघ की पृष्ठभूमि से नहीं थीं। नई शिक्षा नीति तैयार करने और उसे लागू करने में देरी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्मृति से बहुत खुश नहीं था। संघ के संदेशों को समझना आसान नहीं है। संघ शोर–शराबा नहीं करता। यही कारण है कि फिलाहल संघ की पृष्ठभमि वाले प्रकाश जोशी को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। मंत्रालय में स्मृति ईरानी के कार्यकाल के दौरान नई शिक्षा नीति पर काम की शुरुआत हुई। मोदी के कार्यकाल के तीसरे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल श्निशंकश के समय इसे लागू किया गया। शिक्षा मंत्री रहे ष्निशंक की पहचान संघ से आने वाले एक विद्वान की रही है, जो संघ के मकध्सद को आगे ले जा सकते थे। हालांकि, अपने अवैज्ञानिक बयानों को लेकर भी वे विवादों में आए। उन्होंने यहां तक कहा कि चरक ऋषि ने अणु–परमाणु की खोज की थी। कोविड के समय जेईई–नीट की परीक्षा कराए जाने की घोषणा के बाद निशंक के खध्लिाफ काफी ऑनलाइन विरोध हुआ था। विरोध में लोग कोर्ट भी गए, जहां सरकार के पक्ष में फैसला आया। हालांकि, तब बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने से रह गए, जिसे लेकर विवाद हुआ। उनके समय भी आरोप लगे कि नई शिक्षा नीति के जरिए केंद्र सरकार शिक्षा पर नियंत्रण अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने नकार दिया था। शिक्षा मंत्रालय के जरिए मोदी सरकार का सारा जोर संघ को साधने में रहा है, किन्तु शिक्षा के उत्थान के लिए बजट को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इसी कारण शिक्षा मंत्रालय में बजट घटता गया और विवाद बढ़ते गए। केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय की हिस्सेदारी पिछले 12 वर्षों में तेजी से घटी है ।

मोदी का पलायन और राहुल का आगमन, बदलते कल की तस्वीर

विकास

एक बात तो यह कि सरकार मानती है कि पेपर लीक करवाने वाला बड़ा मफिया है और करोड़ों रुपया देने की उसकी हैसियत है। दूसरी सबसे मुख्य बात कि जोर इस पर होना चाहिए कि अब पेपर लीक नहीं होगा। सरकार बात बदल रही है कि अगर होगा तो फिर यह यह करेंगे। बाद में आप कुछ भी करते रहो उससे क्या? समाचार पत्र प्रकाशन ऐसे साहस का व्यक्ति और कोई याद नहीं आता। डा.मनमोहन सिंह ने कहा था– इतिहास मेरे साथ इस मीडिया के मुकाबले बेहतर न्याय करेगा। और इतिहास ने अभी बता दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगाए गए सारे आरोप खत्म कर दिए। लेकिन यहां बात मनमोहन सिंह की नहीं उस शख्स की हो रही है जिसके साथ मीडिया ने मनमोहन सिंह से भी ज्यादा दुश्मनी भरा व्यवहार किया। और केवल मीडिया नहीं था। पूरी सरकार थी उसके पीछे और अंध ाभक्तों की एक बड़ी भीड़। मगर वह शख्स न डिगा, न डरा न रुका। और अब जब उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से परिस्थितियां बदल दी हैं तो कहा जा सकता है कि इतिहास से पहले समय को राहुल के साथ न्याय करना होगा। वह वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जिनके बारे में मीडिया, उनकी पार्टी के लोग और भक्तयह कहते थे कि वे नहीं तो और कौन? उनका ग्राफ गिरना शुरू हो गया है। मोदी एक घटना दुर्घटना के बने नेता हैं। खुद उनकी पार्टी के अटल अडवानी और दूसरे नेताओं की तरह लगातार सार्वजनिक रूप से काम करके उभरे नेता नहीं। गोध ारा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए गुजरात दंगों से पहले उनकी गिनती भाजपा में भी बहुत पिछली पंक्ति के नेताओं में होती थी। केन्द्र में बीजेपी की सरकार थी। अटल, आडवानी, मुरली मनोहर जोशी और इसके बाद की सेंकड केटेगरी के नेताओं की भी लंबी लिस्ट थी। बहुत नाम हैं। जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, प्रमोद महाजन इन्हें आप टाप सेंकड में डाल सकते हैं। इसके बाद नेतृत्व की सेंकड लाइन में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वैंकय्या नायडू जैसे बहुत नाम हैं। मोदी उस समय गिनती में ही नहीं आते थे। मगर गोधरा और उसके बाद गुजरात दंगों का ऐसा उपयोग किया गया कि मोदी सीधे उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी से कैमरे के सामने बहस करने लगे कि कर तो रहे हैं। जब वाजपेयी ने राजधर्म पालन करने की बात कही तो उस समय मुख्यमंत्री मोदी ने यही जवाब दिया था कि– कर तो रहे हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी नहीं कह पाए कि नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने शुरू में लिखा कि एक घटना दुर्घटना से बने उभरे नेता मोदी। और अब एक और घटना आंदोलन से गिरते मोदी। छात्रों के आंदोलन ने मोदी का सारा रौब, रुतबा खत्म कर दिया। वे छात्रों को बुलाकर उनसे बात नहीं कर पा रहे। रील जो गंभीर जिम्मेदार मैसेज का जरिया नहीं मानी जाती उसके द्वारा युवतम पीढ़ी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाय फ्रेन्ड्स बोलने या जेन जी की दूसरी शब्दावली, स्टाइल उपयोग करने से यह पीढ़ी कनेक्ट नहीं होती है। यह होती है प्यार विश्वास और भय रहित माहौल से। मोदी ऊंचे सिंहासन पर बैठकर क्षमादान देने की बात करते हैं। इतिहास में वह घटना किस तरह घटी थी वह अलग बात है। मगर 65 साल से पहले बनी फिल्म मुगले आजम में जैसे शहंशाह अकबर के सामने उस समय की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि सलीम कहते हैं कि मेरे उसूल आपकी माफी के मोहताज नहीं हैं जिल्ले इलाही! वह जिल्ले इलाही की परंपरा आज भी चली आ रही है। शहंशाह अकबर को तो दूसरे कहते थे। मगर यहां तो मोदी खुद ही कहने लगे कि वे नान बायलोजिकल हैं। अवतार पुरुष। जिल्ले इलाही का मतलब भी कुछ इसी दिशा में होता है। ईश्वर का प्रतिनिधि। तो आज के बच्चे उनकी माफी के मोहताज नहीं हैं। उनकी तो मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगें। लाठी, आंसू गैस, करंट मारने वाली लोहे की राड तो सब चलाए ही मगर लड़कियों के साथ जिस तरह शर्मनाक व्यवहार किया गया और पेलेट गन चलाई गई खासतौर से उसके लिए मोदी माफी मांगें। मगर वे उल्टा कह रहे हैं कि मैंने माफ किया। यह वही सर्वशक्तिमान होने के गुमान है जिसमें अकबर माफ करने की बात करता है और सलीम कहते हैं कि न मैं झुकूंगा और आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं लाश में तबदील तो वह लाश भी झुकेगी नहीं। 22 से ज्यादा बच्चे मरे ही हैं। जान दे दी उन्होंने। उस पर मोदी ने क्या कहा। उन्हें भी माफ करने की बात कहकर उन बच्चों के मां–बाप के जख्मों को और गहरा कर सकते हैं। बच्चों का कसूर क्या था? क्यों करनी पड़ी उन्हें खुदकशी? जिस कारण कि पेपर लीक होना उस पर तो प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। अब पेपर लीक होगा तो और कड़ी सजा होगी का विधेयक संसद में पहुंचा दिया। खुद नहीं आए उस पर बोलने। समाचार पत्र प्रकाशन लेकिन जैसा हमने आज की बात शुरू की है कि उसने अपनी हिम्मत, मेहनत और छात्रों के प्रति अपनी संवेदना, जुड़ाव से बाजी पलट दी राहुल का कहना है कि प्रध ाानमंत्री मोदी लोकसभा में मेरे सामने

नहीं आ सकते। संसद के बजट सत्र के बाद इस चल रहे मानसून सत्र में भी यह बात साबित हो गई। पेपर लीक विधेयक पर नहीं आए और उस वंदे मातरम बिल पर भी नहीं जो उनकी फेवरेट पिच रही है। अभी छह महीने पहले वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस पर इस तरह बरसे थे जैसे उनके संगठन का गीत रहा हो। उससे तो कांग्रेस के हर अधिवेशन शुरू होता है। लेकिन अब वंदे मातरम या कोई भी ऐसा इशु जिससे उन्हें लगता है कि भावनाएं भड़काई जा सकती हैं सब लाइम लाइट में लाने की कोशिश करते हैं। मगर इस बार वंदे मातरम जिसको कानून बना रहे हैं पर बोलने भी लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में नहीं आए। नीट पेपर लीक के बाद से साफ दिख रहा है कि मोदीजी परिस्थितियों पर नियंत्रण खोते जा रहे हैं। उनकी कोशिश सफल नहीं हो रही है। छात्रों को माफ करने की बात उलटी पड़ रही है। इसी तरह पेपर लीक का विधेयक जो एक संशोध ान विधेयक ही है लीक रोकने की बात नहीं करता है। लीक हो जाने पर पहले के मुकाबले ज्यादा सजा और जुर्माने का बात करता है। जुर्माना करोड़ों में। एक बात तो यह कि सरकार मानती है कि पेपर लीक करवाने वाला बड़ा मफिया है और करोड़ों रुपया देने की उसकी हैसियत है। दूसरी सबसे मुख्य बात कि जोर इस पर होना चाहिए कि अब पेपर लीक नहीं होगा। सरकार बात बदल रही है कि अगर होगा तो फिर यह यह करेंगे। बाद में आप कुछ भी करते रहो उससे क्या? 22 स्टूडेंट जिन्होंने जान दी इसके लिए नहीं रुक पाए न कि लीक करने वालों की सजा कड़ी की जाएगी।

छात्रों और युवाओं के आंदोलन का अपमान

अजीत द्विवेदी

आपदा को अवसर बनाने की कला में माहिर राइटविंग के कई इन्फ्लूएंसर और हर घटनाक्रम में साजिश का पहलू खोजने वाले मोदी विरोधी दोनों एक साथ दावा कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर हुआ आंदोलन प्रायोजित था और इस आंदोलन से सरकार को बहुत फायदा हुआ है। कहा जा रहा है कि सरकार बड़ी सफलता के साथ राममंदिर के चढ़ावा चोरी और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का मुद्दा लोगों के जेहन से निकालने में कामयाब हो गई। सोचें, यह कितना बेसिरपैर का तर्क है? चढ़ावा चोरी अब भी लोगों के जेहन में है और ई–20 पेट्रोल का मामला लोगों के अपने जीवन और उनकी जेब से जुड़ा है इसलिए वह भी ध्यान से नहीं निकलने वाला है। ई–20 पार्टी नाम से एक संगठन बन गई है, जिसकी ओर से आंदोलन की तैयारी की जा रही है। फिर भी अगर यह प्रायोजित आंदोलन था तो कह सकते हैं कि सरकार ने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए गर्दन कटवाने का काम किया है।

असल में आंदोलन को प्रायोजित बताने वाले लोग छात्रों और युवाओं के इस आंदोलन का अपमान कर रहे हैं। वे छात्रों और युवाओं को सरकार या किसी और के हाथ का प्यादा साबित करने में लगे हैं। हकीकत यह है कि इस तरह की बात करने वालों को अपनी नई पीढ़ी के बारे में कोई अंदाजा नहीं है और वे उन्हें समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि जितना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर था उससे कितना बड़ा आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। युवाओं ने इंस्टाग्राम को ही जंतर मंतर बना दिया था, जहां वे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें और उनके आंदोलन को डिमीन करने या अपमानित करने से पहले उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें पुराने मुहावरों या मूल्यों के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। उनके सभी बुनियादी मूल्य बदल गए हैं, उन्हें पुराने फॉर्मूले से आप पहचान नहीं पाएंगे। उनके लिए कमाई और सफलता की धारणा बदल गई है। वे बिना ऑफिस स्पेस के ऑफिस चलाते हैं, बिना पारंपरिक मुद्रा के कमाई करते हैं, उनकी सफलता उम्र और अनुभव का इंतजार नहीं करती है। जन्म के साथ मिली पहचान की धारणा को उन्होंने काफी हद तक तोड़ दिया है। इस रूप में उन्हें स्वीकार कीजिए और उन्होंने जो हासिल किया है उसका उत्सव मनाइए। इसके उलट यह प्रचार करना मूर्खता है कि सरकार ने या किसी और ने आंदोलन को प्रभावित किया। वास्तविकता यह है कि इस आंदोलन से सरकार को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उलटे सरकार ने अपनी साख, अपनी लोकप्रियता और अपना समर्थन गंवाया है। एक पूरी पीढ़ी की स्मृतियों में दशकों तक जंतर मंतर की तस्वीरें रहेंगी। उनको याद रहेगा कि जब वे अपनी तकलीफों का समाधान मांगने जंतर मंतर पर गए थे तब सरकार ने उनके ऊपर लाठियां चलवाई थीं, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, उनको घायल करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। उन्हें याद रहेगा कि उनकी रचनात्मकता और लोकप्रियता से घबराई सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया था। उनके सहयोग के लिए बढ़े हाथों को कानूनी दांव पेंच के जरिए रोका था। जंतर मंतर की तरफ बढ़ने वाले कदमों की रफ्तार रोकने के लिए कई दिन तक मेट्रो बंद रखे गए थे। फूड डिलीवरी ऐप्स को रोका गया था। जंतर मंतर के आसपास के दुकानदारों को धमकाया गया था। छात्रों के ऊपर मुकदमे किए गए थे। ये तमाम बातें नई पीढ़ी के युवाओं की स्मृति में स्थायी रूप से दर्ज रहेंगी। जिस तरह से आजादी के बाद की पीढ़ी की यादों में आजादी की लड़ाई के मूल्य दर्ज थे उसी तरह इस पीढ़ी की यादों में पेपर लीक से लेकर पुलिस के लाठी चलाने तक की घटना दर्ज रहेगी। उनका राजनीतिक और मतदान व्यवहार इससे प्रभावित होगा। राजनीतिक पार्टियां आमतौर पर मानती हैं कि एक बार आंदोलन खत्म होने के बाद सब कुछ बदल जाता है और पुराने ढर्रे पर लौट आता है। याद करें कैसे किसान आंदोलन खत्म होने के बाद वापस लौटे किसानों ने अपनी किसान वाली अस्मिता छोड़ दी थी और घर में खूंटी पर टंगी जाति और धर्म वाली अस्मिता ओढ़ ली थी। वैसे ही भाजपा को लग रहा होगा कि छात्र और युवा भी घर लौटेंगे तो प्रदर्शनकारी श्जेन जी्य वाली अस्मिता खूंटी पर टांग देंगे और जाति व धर्म वाली अस्मिता ओढ़ लेंगे। हो सकता है कि कुछ युवाओं के साथ ऐसा हो लेकिन व्यापक रूप से उनके व्यवहार में बदलाव होने की संभावना कम है। ऐसा होने के कई कारण हैं। एक, युवाओं ने बहुत ठोस कारण से आंदोलन शुरू किया था। जब उनकी पीड़ पर्वत सी हो गई थी तब वे सड़क पर उतरे थे। अभी तुरंत उनकी इस पीड़ा का समाधान नहीं होने जा रहा है। दो, डिजिटली कनेक्टेड इस दौर में उनके आंदोलन की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। वे इसकी सफलता को लंबे समय तक याद रखना चाहेंगे। तीन, उनका परिवार भी किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़ा था। इसलिए अपनी अस्मिता बदलने के लिए उनके ऊपर अब कोई बाहरी दबाव नहीं होगा। चार, संसदीय लोकतंत्र में संविधानेत्तर उपकरणों से जो बदलाव होते हैं उनसे उम्मीदें तो बहुत बड़ी होती हैं लेकिन उनके पूरा नहीं होने पर निराशा भी उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए युवाओं का उत्साह जिन उम्मीदों से बढ़ा है अगर वो निराशा में बदलती हैं तो ज्यादा मुश्किल होगी। नेपाल में सबने देखा है कि कैसे छह महीने से भी कम समय में श्जेन जी्य का अपनी ही बनाई सरकार से मोहभंग हुआ। सरकार को भी इसका अंदाजा है तभी उसने तात्कालिक उपाय और दीर्घावधि के लिए जरूरी उपाय एक साथ शुरू किए हैं। एक तरफ पेपर लीक रोकने के लिए 2024 में लाए गए कानून को दो साल के अंदर ही संशोधित किया जा रहा है और ज्यादा सख्त कानून बनाया जा रहा है। इसका मकसद युवाओं को तात्कालिक संतोष देना है। लेकिन साथ ही एक उच्चाधि ाकार प्राप्त कमेटी बना कर परीक्षा व्यवस्था की संस्थागत और संरचनागत समस्याओं को दूर करने की पहल भी की गई है। सरकार ने बहुत सोचे समझे तरीके से इस कमेटी की अध यक्षता के लिए नंदन नीलेकणी का नाम तय किया है। सरकार को पता था कि उनको बनाए जाने पर यह सवाल उठेगा कि कांग्रेस के नेता रहे व्यक्ति को सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन इसी से इस पूरी पहल की विश्वसनीयता भी बनेगी। सरकार की पहली चिंता परीक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयासों की विश्वसनीयता बहाल करने की है। वह नंदन नीलेकणी के नाम से होगा। सरकार को धारणा के स्तर पर इसका लाभ मिल सकता है। परंतु अभी अगर कोई कहता है कि यह आंदोलन सरकार या किसी और द्वारा प्रायोजित किया गया था या कॉकरोच जनता पार्टी भी भाजपा का उपक्रम है या सोनम वांगचुक सरकार के एजेंट थे और इन सबको आगे कर सरकार ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी या पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के मामले को सार्वजनिक विमर्श से हटा दिया है तो उसे वास्तविक हालात की जानकारी नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार को श्जेन जी्य के इस आंदोलन से बड़ा नुकसान हुआ है। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी जो विरासत बना रहे थे उस पर संकट आया है। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझ रहे हैं। वे किसी भ्रम में नहीं हैं। इसलिए इसको ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं। कामयाबी कितनी मिलेगी, कह नहीं सकते हैं।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आधार सेवाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर।,जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में आधार सेवाओं की प्रगति, 0–5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन, 5–7 वर्ष एवं 15–17 वर्ष आयु वर्ग के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, लंबित प्रकरणों तथा आधार केंद्रों के संचालन की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि आधार नामांकन एवं अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के कार्य में तेजी लाई जाए तथा प्रत्येक पात्र नागरिक को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण आधार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर बल दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने न्व्।ए के ।कींत ।चच के व्यापक प्रचार–प्रसार के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को आधार एप के माध्यम से उपलब्ध सुविधाओं, जैसे डिजिटल आधार प्रोफाइल, सुरक्षित क्यूआर कोड आधारित पहचान सत्यापन, आधार विवरण साझा करने की सुविधा तथा अन्य उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी वि.ध्रा. परमानन्द झा, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, UIDAI के प्रतिनिधि तथा आधार नामांकन एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर बनी रणनीति

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी मछलीशहर द्वारा सीहीपुर स्थित जिला कार्यालय पर हर घर तिरंगा अभियान के निमित्त जिला कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 10 से 14 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के निमित्त पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाने की रणनीति बताई गई।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि एवं जिला प्रभारी, काशी क्षेत्र के क्षेत्र महामंत्री संतोष सिंह पटेल ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल किसी घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता, वीर शहीदों के बलिदान और राष्ट्र की एकता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अभियान है। तिरंगा भारत की आन, बान और शान का प्रतीक है। इसके तीनों रंग और अशोक चक्र देश के गौरवशाली इतिहास, त्याग, शांति, समृद्धि और निरंतर प्रगति का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज जन–जन का अभियान बन चुका है। इस अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और देश के प्रति अपने दायित्वों की भावना और अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गांव–गांव, बूथ–बूथ और घर–घर जाकर लोगों को अभियान से जोड़ें तथा स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रभक्ति के उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करें। अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष डॉ. अजय कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता संगठन की शक्ति के साथ हर घर तिरंगा अभियान को जनअभियान बनाने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि तिरंगा किसी राजनीतिक दल का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे देश की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। यह हमें उन असंख्य

स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों के त्याग की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान कार्यकर्ता समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलें और लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने मंडल, शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर के पदाधिकारियों को अभियान की सफलता के लिए जिम्मेदारियां सौंपते हुए कहा कि संगठन की सक्रियता से हर घर तक राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचना चाहिए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज देश आत्मनिर्भरता, विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति अपने संकल्प को दोहराने का अवसर देता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अभियान को केवल औपचारिक कार्यक्रम न मानकर इसे जनभावना से जोड़ें और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करें। कार्यक्रम को पूर्व विधायक डॉ हरेंद्र प्रसाद सिंह ने भी संबोधित किया। संचालन अभियान जिला संयोजक,जिला उपाध्यक्ष मोहन राजभर ने किया। इस अवसर पर भूमि विकास बैंक निदेशक डॉ अजय सिंह, अखिलेश सिंह,बांके बिहारी सिंह,दिनेश सोनकर,संतोष मिश्रा,स्कन्द पटेल,अखिल प्रताप सिंह,अनुपमा राय,केपी मिश्रा,राजेश सिंह,अतुल कुमार पांडेय, रणविजय सिंह, हरिश्चंद्र मौर्या,ऊषा किरण, मीना पटेल,कमलेश राय,सोनी जायसवाल,हरिराम पाल,सुदर्शन सिंह,धनंजय कश्यप,अजीत सोनकर,रिशु सिंह रिद्धिमा,संतोष उपाध्याय,शिवम पाल, विशाल शुक्ला,वैभव सिंह आदि उपस्थित रहे।

वीर बलिदानियों की स्मृति में, शौर्य रत्न समारोह का आयोजन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ।कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हंगामा न्यूज चौनल के द्वारा, वीर बलिदानियों की स्मृति में, शौर्य रत्न समारोह,,का आयोजन किया गया,, बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ सेवा के दौरान विषम परिस्थितियों में युद्ध और युद्ध जैसे हालात में मां भारती की सेवा करने वाले वीर पूर्व सैनिकों को श्री मती नम्रता पाठक पत्नी श्री बृजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश , के द्वारा सम्मानित किया गया,, समारोह की स्मृति अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद लखनऊ, अवध प्रान्त के साथियों के साथ,, जय हिन्द,,वन्दे मातरम्,,

लेफ्टिनेंट कर्नल बीरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सभी सम्मानित महानुभावों को सादर नमन ध्जयश्रीराम ,संगठन से जुड़े सभी आदरणीयों को राजभवन, लखनऊ के सामने विश्वेशराया हॉल में लखनऊ जिले की कार्यकारिणि द्वारा 11 बजे से आमंत्रित किया गया था जिसमें संगठन से जुड़े अनेक राष्ट्रभक्त सदस्यों ध पदाधिकारियों ने अपनी सहभागिता दी.यह प्रोग्राम हंगामा न्यूज चौनल द्वारा आयोजित किया गया था जो कि कारगिल विजय दिवस पर सैनिकों के सम्मान के लिए भी था. वहां उपस्थित हमारे संगठन के सम्मान पाने वाले सभी सैनिकों के साथ कार्यक्रम की झलकियां प्रस्तुत हैं. 2. उपरोक्त कार्यक्रम के पश्चात् सभी सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल तोमर साहब के कार्यालय में एकत्र हुए जहाँ पर लखनऊ जिले की नई कार्यकारिणी, अवध प्रान्त की हरदोई में 23 अगस्त को होने वाले AGM, प्रदेश की ।ळड, संगठन की कोष वृद्धि, आदि आदि के बारे में विचार एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये व इस सभी उपस्थित महानुभावों ने अपने अपने विचार रख्खे. आज की बैठक में हमारे संगठन में एक नये सदस्य का स्वागत हुआ जिनका परिचय निम्नवत है ।–

सूबेदार मेजर H- K- L- Singh .बैठक के अंत में शांतिपाठ के बाद ग्रुपिंग हुई जिसकी झलकी भी प्रस्तुत है. जयहिंद ,वन्देमातरम. अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिंदाबाद. हमें अपने गौरवशाली संगठन पर अपार गर्व है. ।

जौनपुर का ऐतिहासिक चेहलुम अकीदत व अनुशासनपूर्ण माहौल में संपन्न, 'या हुसैन अलविदा' की सदाओं के बीच ताजिए सुपुर्द–ए–खघक

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में शीराज–ए–हिन्द जौनपुर का ऐतिहासिक चेहलुम अकीदत, गम और अनुशासनपूर्ण माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इमामबाड़ा शेखघ मुहम्मद इस्लाम मरहूम से निकला पारंपरिक तुर्बत एवं ताजियों का जुलूस निर्धारित मार्गों से होकर सदर इमामबाड़ा पहुँचा, जहां ष्या हुसैन अलविदाष की सदाओं के बीच ताजियों एवं तुर्बत को सुपुर्द–ए–खघक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दो अगस्त की रात इस्लाम चौक पर ताजिया रखने के साथ हुई। शब्बेदारी की मजलिस में डॉ. कमर अब्बास ने जाकिरी की, जबकि पूरी रात विभिन्न अंजुमनों ने नौहाखघ्वानी और मातम के माध्यम से कर्बला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रातःकालीन मजलिस में बिलाल हसनैन ने जाकिरी की तथा अंजुमन गुलशन–ए–इस्लाम (रजि.) ने आग में दहकती जंजीरों का मातम पेश किया। कार्यक्रम का संचालन सैय्यद अकबर हुसैन जैदी एडवोकेट एवं तालिब जैदी ने किया। तीन अगस्त को मौलाना सैय्यद नदीम जैदी फैजाबादी ने मजलिस को संबोधित किया। इसके बाद ऐतिहासिक तुर्बत का जुलूस पानदरीबा रोड, हमाम दरवाजा, काजी की गली और पुरानी बाजार होते हुए सदर इमामबाड़ा पहुँचा। इस चरण का संचालन सैय्यद कबीर जैदी ने किया। जौनपुर का यह ऐतिहासिक चेहलुम देशभर में मनाए जाने वाले चेहलुम से एक दिन पूर्व आयोजित किया जाता है। इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा के कारण विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में जायरीन इसमें शामिल होते हैं। मान्यता है कि इमामबाड़े के संस्थापक शेखघ मुहम्मद इस्लाम मरहूम के जेल में होने के कारण नौ मोहर्रम का ताजिया नहीं उठ सका था। उनकी रिहाई के बाद 19 सफर को ताजिया उठाकर सदर इमामबाड़ा में सुपुर्द–ए–खघक किया गया, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में चेहलुम के समस्त इंतजामात मीर मुजफ्फर हुसैन जैदी के खघनदान द्वारा किए जाते हैं।

एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग उठाई, डीएम को सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश के एमबीबीएस इंटर्न एवं मेडिकल छात्रों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सरकार से मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की। इंटर्न्स ने वर्तमान में मिलने वाले 12 हजार रुपये प्रतिमाह के स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की अपील की। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में मिलने वाला स्टाइपेंड देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। मौजूदा महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों में 12 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि सम्मानजनक जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है।

इंटर्न्स ने बताया कि एमबीबीएस की साढ़े चार वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप चिकित्सा प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इस दौरान वे अस्पतालों में वार्ड ड्यूटी, इमरजेंसी सेवाएं, नाइट ड्यूटी, मरीजों की निगरानी तथा विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाओं में चिकित्सकों की सहायता करते हैं। साथ ही अस्पताल के नियमित संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कई बार निर्धारित समय से अधिक कार्य भी करते हैं। छात्रों का कहना है कि वर्तमान स्टाइपेंड से आवास, भोजन, परिवहन, अध्ययन सामग्री, इंटरनेट तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे आवश्यक खर्च पूरे करना कठिन हो जाता है। इसके चलते अधिकांश इंटर्न अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी परिवार पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। इंटर्न्स ने सरकार से मांग की कि उनके कार्य, जिम्मेदारियों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए, ताकि वे आर्थिक दबाव से मुक्त होकर बेहतर ढंग से चिकित्सा सेवाएं दे सकें।

डीएम की अध्यक्षता में जिला ओटीडी सेल की प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला ओटीडी सेल की प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के सकल जिला घरेलू उत्पाद से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे आंकड़ों एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा, निर्माण, बैंकिंग, वित्तीय सेवायें तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़े विभागों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के आर्थिक विकास का सही आकलन तभी संभव है, जब सभी विभाग अपने–अपने क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को पूर्ण पारदर्शिता, शुद्धता एवं समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आंकड़ों के संकलन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे तथा विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी सूचनाएं निर्धारित समयावधि में जिला अर्थ और संख्या अधिकारी,कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएं।बैठक में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यान एवं वानिकी विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई। खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, गन्ना, फल, सब्जी, मसाला एवं पुष्प उत्पादन के साथ–साथ दुग्ध, मांस, अंडा, मत्स्य एवं टिम्बर उत्पादन से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को वास्तविक प्रगति के अनुरूप डेटा अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। द्वितीयक क्षेत्र की समीक्षा के दौरान उन्होंने उद्योग, श्रम, विद्युत, जलापूर्ति एवं निर्माण कार्यों से संबंधित प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों, एमएसएमई, जीएसटी संग्रह, औद्योगिक गतिविधियों तथा स्थानीय निकायों के राजस्व संबंधी आंकड़ों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सभी आंकड़े अद्यतन एवं प्रमाणिक हों। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, पर्यटन, होटल, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, पंजीकृत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, जीएसटी संग्रह, पर्यटकों की संख्या, बस परमिट, वाणिज्यिक वाहनों, बैंक ऋण एवं जमा राशि सहित विभिन्न आर्थिक संकेतकों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सूचनाओं के आधार पर जनपद की आर्थिक गतिविधियों का समुचित मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए सभी विभाग नियमित रूप से आंकड़ों का सत्यापन करते हुए समय से उपलब्ध कराएं। बैठक में जनपद के सकल जिला घरेलू उत्पाद सहित अन्य संबंधित उपलब्ध आंकड़ों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भविष्य की योजनाओं एवं विकास कार्यों के लिए आर्थिक संकेतकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तथा डेटा की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि ओटीडी सेल से संबंधित सूचनाओं का संकलन नियमित रूप से किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लंबित सूचना को तत्काल उपलब्ध कराया जाए, जिससे जनपद के आर्थिक विकास का यथार्थ एवं अद्यतन आकलन समय पर शासन को प्रेषित किया जा सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी (वि०ध्रा०) परमानंद झा, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ अरुण कुमार यादव, सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जौनपुर में झमाझम बारिश से मिली गर्मी से राहत, जलभराव ने खोली नगर पालिका के दावों की पोल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। जौनपुर जनपद में बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण उमस और गर्मी से सोमवार देर रात लोगों को उस समय राहत मिली, जब अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि, बारिश ने नगर पालिका परिषद की तैयारियों की भी पोल खोल दी। शहर के कई प्रमुख मार्गों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों पर पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान कई स्थानों पर सड़कें तालाब जैसी नजर आईं। जगह–जगह बने गड्ढों में दोपहिया और चारपहिया वाहन फंसते रहे, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। शहर की कई सड़कें अब भी गड्ढामुक्त नहीं हो सकी हैं, जबकि प्रशासन और नगर पालिका की ओर से सड़कें दुरुस्त करने तथा जलनिकासी की व्यवस्था बेहतर होने के दावे किए जाते रहे हैं। बारिश के बाद सामने आई जलभराव की समस्या ने नगर पालिका परिषद की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नागरिकों ने जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है। बारिश के कारण नगर के रूहट्टा, काली कुट्टी,ओलन्दगंज पोलिटेक्निक चौराहे नई गंज सिटी स्टेशन, बदलापुर पड़ाव,मछलीशहर पड़ाव आदि क्षेत्रों में भारी जलभराव रहा जो सुबह तक निकल पाए।इस मामले में जानकारी लेने पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मनोरमा मौर्य ने बताया कि बारिश के कारण नालियां बंद हो गई थी कर्मचारियों को लगाकर सफाई कार्य किया गया है नालों को सफाई पहले कराया जा चुका है पानी कही रुकने नहीं पाएगा।

गोरखपुर की घटना के विरोध में जौनपुर में प्रदर्शन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई व एक करोड़ मुआवजे की मांग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में गोरखपुर में 10 वर्षीय बच्ची के कथित अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में मंगलवार को भारतीय नाई कल्याण विकास सेवा समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में समिति ने आरोप लगाया कि बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव रोहिन नदी में फेंक दिया गया। मामले के आरोपी सिपाही अभिषेक यादव के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर पॉक्सो अधिनियम एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत शीघ्र कठोरतम दंड दिए जाने की मांग की गई। समिति ने यह भी मांग की कि आरोपी की पूर्व में हुई सेवा बहाली की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, पर्याप्त सुरक्षा, न्यायिक सहयोग तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश के जिला अस्पतालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और रात्रि गश्त को प्रभावी बनाने की भी मांग उठाई। इसके अलावा पुलिस भर्ती, तैनाती और बहाली की प्रक्रिया में चरित्र सत्यापन को और अधिक सख्त किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई से ही आमजन का कानून व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होगा।

अनुशासन से ही बनता है श्रेष्ठ व्यक्तित्व - कुलपति प्रो. वंदना सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान में बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम का शुभारंभ मंगलवार को उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह एवं अन्य अतिथियों का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। इनडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने कहा कि अनुशासन ही विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अनुशासित विद्यार्थी ही अपने ज्ञान, व्यक्तित्व और चरित्र का समुचित विकास कर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन, शोध, खेलकूद तथा सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा केवल कानून का अध्ययन नहीं, बल्कि न्याय, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति संवेदनशील नागरिक बनने की प्रक्रिया है। संस्थान में आयोजित प्रथम तकनीकी सत्र में डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर ने ष्साइबर सुरक्षाष विषय पर व्याख्यान देते हुए विद्यार्थियों को डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन वित्तीय लेन–देन में बरती जाने वाली सावधानियों, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा तथा साइबर अपराध की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवा स्वयं जागरूक रहें और अपने परिवार को भी साइबर अपराधियों से सुरक्षित रखने में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। विधि के विद्यार्थियों को साइबर अपराधों की प्रकृति और कानूनी पहलुओं को गहराई से समझने की आवश्यकता है। द्वितीय सत्र में आयोजित हैप्पीनेस एवं मेडिटेशन कार्यक्रम के अंतर्गत श्री आनंद राय ने योग, मेडिटेशन तथा प्रेरणादायक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, मानसिक एकाग्रता एवं तनावमुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) के साथ–साथ बी.एससी. एग्रीकल्चर एवं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स (बी.पी.ई.एस.) के नवप्रवेशी विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत डॉ. वनिता सिंह ने किया। विभागाध्यक्ष एवं निदेशक प्रो. विनोद कुमार ने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉ. प्रियंका कुमारी, जय सिंह एवं रजनीश सिंह का विशेष सहयोग रहा तथा संचालन डॉ.अनुराग मिश्र ने किया।

कमिश्नर राजेश कुमार ने डीएम शशांक त्रिपाठी व अन्य अधिकारियों के साथ किया चौदहकोसी एवं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।कमिश्नर राजेश कुमार ने डीएम शशांक त्रिपाठी ने चौदहकोसी एवं पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर चल रहे वृक्षारोपण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।उन्होंने नगर आयुक्त जैनेंद्र,उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण श्री अनुराज जैन,प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) प्रखर गुप्ता, अपर जिलाधिकारी (नगर) योगानंद पांडे तथा अपर जिलाधिकारी (वि.ध्रा.) अमित कुमार भट्ट सहित अन्य अधिकारी के साथ निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने पौधरोपण की गुणवत्ता, पौधों के संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था तथा नियमित देखरेख की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगाए गए प्रत्येक पौधे का समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि वृक्षारोपण अभियान के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें।कहा कि परिक्रमा मार्ग धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर लगाए जा रहे पौधे भविष्य में श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों को स्वच्छ वातावरण, हरित आवरण तथा छायादार मार्ग उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पौधों की नियमित निगरानी, समयबद्ध सिंचाई, सुरक्षा एवं आवश्यक रखरखाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे पौधों का अधिकतम जीवित प्रतिशत बना रहे।

डीडीयू-जीकेवाई के प्रथम प्रशिक्षण दल का हुआ भव्य स्वागत

अयोध्या।डीडीयू–जीकेवाई के प्रथम प्रशिक्षण दल का भव्य स्वागत हुआ।इस मौके पर डॉ. वी. के. वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डीडीयू–जीकेवाई के प्रथम प्रशिक्षण दल का उत्साहपूर्ण एवं पारंपरिक रीति–रिवाजों के साथ स्वागत किया गया।कार्यक्रम मे जिला समन्वयक चंद्रशेखर सिंह एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक नीरज सिंह अम्बेडकर नगर की गरिमामयी उपस्थिति रही। जिला समन्वयक चंद्रशेखर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रशिक्षणार्थियों से भरी बस को अकबरपुर से प्रशिक्षण केंद्र के लिए रवाना किया।प्रशिक्षण केंद्र पहुँचने पर खुशी वर्मा, कंचन यादव, श्री संजीव जी एवं दिव्या ने सभी प्रशिक्षणार्थियों का तिलक लगाकर एवं पुष्पों के साथ आत्मीय स्वागत किया।कार्यक्रम में प्रोजेक्ट हेड सत्य देव श्रीवास्तव,संदीप सिंह, विपिन, आशा, राज, ऋचा सहित पूरी टीम उपस्थित रही। इस संबंध में कार्यक्रम के प्रोजेक्ट हेड सत्यदेव श्रीवास्तव ने बताया कि यह 3 माह का आवासीय प्रशिक्षण भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को आवास (हॉस्टल), भोजन, यूनिफॉर्म, पुस्तकें, अध्ययन सामग्री एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ना तथा आत्मनिर्भर बनाना है। सभी प्रशिक्षणार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति एवं जिला मिशन समिति की बैठक

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' मंगलवार को स्वामी विवेकानन्द सभागार मे जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति एवं जिला मिशन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं गत वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्यों की पूर्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने खेत तालाब योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मार्जिनल बांध एवं पेरिफेरल बांध से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की तथा निर्देश दिये कि इन बाधों पर वृक्षारोपण कराया जाये तथा कराए गए वृक्षारोपण कार्यों के फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाये। जिलाधिकारी ने समतलीकरण कार्यों की भी समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि जिन विकास खंडों में अभी तक समतलीकरण अथवा अन्य भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य नहीं कराए गए हैं, वहाँ चालू वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर कार्य स्वीकृत कराकर समयबद्ध रूप से पूर्ण कराए जाएँ। उन्होंने विभाग द्वारा कराए गए सभी कार्यों का स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध एवं शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे अधिकाधिक किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नेहा व्याडवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुश्री संस्कृति त्रिवेदी, उपनिदेशक कृषि, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी प्रथम इन्द्रसेन नाथ, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी द्वितीय डॉ0 निधि राठौर तथा सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत

अयोध्या।सोमवार को थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र मे संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोरी की मौत हो गई।क्षेत्र के कंधरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोरी की मौत से हड़कंप मच गया।किशोरी का शव घर के कमरे में छत के कुंडे से लटका मिला।सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

मिशन शक्तिअभियान के तहत महिला थानाध्यक्ष के नेतृत्व मे उप निरीक्षक प्रिया ने छात्राओं को किया जागरुक

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।सोमवार को एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर तथा मिशन शक्ति फेज 5 के नोडल प्रभारी व एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के निर्देश पर सीओ सिटी श्रीयेश त्रिपाठी की देखरेख मे महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के नेतृत्व मे उप निरीक्षक प्रिया ने मिशन शक्ति के तहत शहर के विभिन्न कॉलेज और चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया।उन्होंने कॉलेज तथा चौक सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर छात्राओं व महिलाओ को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया।इस मौके पर उन्होंने मिशन शक्ति अभियान फेज फाइव के तहत सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी देते हुए बताया कि जिससे कभी भी संकट के समय आप अपनी सुरक्षा कर सकती हैं।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बालिकाओं से कहीं।उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए जहां एक तरफ उनके विकास को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण सुकन्या समृद्धि योजना सहित एक से बढ़कर एक कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चल रही हैं।इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद बालिकाओं को पंपलेट व बैनर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना का अंदेशा हो तो बिना झिझक अपने नजदीकी पुलिस कर्मियों, महिला थाना तथा अपने परिजनों को फोन पर बताये।इस मौके पर उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।

जनसुनवाई संभव में आठ शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम पर दिया जोर

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। अयोध्या नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में नागरिकों की 16 शिकायतों मे से आठ का मौके पर ही निस्तारण किया।शेष शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।जनसुनवाई की अध्यक्षता करते हुए महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि वर्षाकाल को देखते हुए नगर में जलभराव वाले स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर एंटी–लार्वा दवा का छिड़काव कराया जाए।ताकि मच्छरजनित बीमारियों का प्रकोप न बढ़े और नगरवासियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।जनसुनवाई में सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जलभराव, पेयजल आपूर्ति, सीवर लाइन की खुदाई तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई की गई।इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त भारत भार्गव, सुमित कुमार सहित नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

आयुर्वेद की दृष्टि में संचारी रोगों की रोकथाम पर विचार गोष्ठी आयोजित'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से ष्आयुर्वेद की दृष्टि में संचारी रोगष विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सचिव डॉ. विजय जौहरी ने की । उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में संचारी रोगों का वर्णन ष्औपसर्गिक रोगष के रूप में किया गया है। आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने ऐसे रोगों का उल्लेख किया है जो दूषित वायु, जल, भोजन तथा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के आयुष विभाग की मंशानुसार आयुर्वेद को जनस्वास्थ्य से जोड़ते हुए संचारी रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन एवं जनजागरूकता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन भी इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप स्थानीय स्तर पर जनजागरण एवं स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संचारी रोग नियंत्रण अभियान में आयुर्वेद चिकित्सकों की सक्रिय सहभागिता से जनजागरूकता बढ़ेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोगों की प्रभावी रोकथाम संभव होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ददरौल के आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. गौरव गुप्ता ने कहा कि वर्षा ऋतु में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, संतुलित आहार, ऋतुचर्या तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ बनाना अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य केवल रोग का उपचार नहीं, बल्कि रोग उत्पन्न होने से पहले ही उसकी रोकथाम करना है। उन्होंने आमजन से आयुर्वेदिक जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. रोहित वर्मा ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम में जनसहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित भोजन एवं आयुर्वेद के निवारक सिद्धांतों का पालन कर डेंगू, मलेरिया तथा अन्य मौसमी संक्रामक रोगों के प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य है। गोष्ठी में डॉ राजेन्द्र प्रकाश सक्सेना, डॉ हितेश गुप्ता, डॉ रवि सक्सेना, डॉ रवि वर्मा, डॉ बृजेश गुप्ता सहित अनेक आयुर्वेद चिकित्सक उपस्थित रहे। अंत में सभी चिकित्सकों ने जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने तथा आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य जागरूकता को जन–जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया।

शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाना उल्टे शिक्षिका पर पड़ा भारी,दोषी मिलने पर प्रथम दृष्टया शिक्षिका को बीएसए ने किया निलंबित

रुदौली/अयोध्या।रुदौली शिक्षा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय करीमपुर में छात्राओं के माध्यम से शिक्षक पर गंभीर आरोप लगवाकर वीडियो वायरल कराने का मामला जांच में पूरी तरह पलट गया।जिस शिक्षिका ने विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक श्री प्रकाश पाठक सहायक अध्यापक के खिलाफ शिकायत बीएसए कार्यालय पर दर्ज कराई थी।इसकी जांच के लिए बीएसए लालचंद ने तीन सदस्य कमेटी का गठन किया था।वही विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाई गई।जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी लालचंद्र ने संबंधित शिक्षिका कोमल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर ब्लॉक संसाधन केंद्र पूरा बाजार से संबंधा कर दिया।साथ ही साथ उन्होंने विभागीय जांच अधिकारी को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट अपने के आदेश दिए हैं। बताते चले यह मामला उसे समय सुर्खियों में आया जब सोशल मीडिया पर जब सोशल मीडिया पर विद्यालय की कुछ छात्राओं का वीडियो वायरल हुआ।वीडियो में सहायक अध्यापक श्री प्रकाश पाठक पर अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए गए थे।मामला तूल पकड़ने पर बीएसए ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर पूरे प्रकरण की जांच कराई।जब जांच समिति ने विद्यालय पहुंचकर छात्र–छात्राओं,शिक्षकों,कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए।उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट बीएसए को सौंपी। इस संबंध में बीएसए लालचंद ने कहा कि जांच समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में सहायक अध्यापक श्री प्रकाश पाठक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।जबकि शिकायतकर्ता शिक्षिका की भूमिका प्रथम दृष्टया दोषपूर्ण पाई गई।इसके बाद विभाग ने उनके विरुद्ध निलंबन कर शिक्षिका कोमल को विभागीय जांच पूरी होने तक ब्लॉक संसाधन केंद्र पूरा बाजार संबद्ध किया गया है। सूत्रों के अनुसार विद्यालय में विज्ञान विषय के दो शिक्षक कार्यरत हैं। विभागीय स्तर पर लागू नई व्यवस्था के तहत शिक्षिका के स्थानांतरण का प्रस्ताव भी चर्चा में रहा। विभागीय जांच में केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। वही सहायक अध्यापक श्री प्रकाश पाठक ने बीएसए द्वारा किए गए कार्यवाही पर संतोष जताते हुए बताया कि ष्मुझे शुरू से ही विभागीय जांच पर पूरा विश्वास था।मैंने जांच समिति के समक्ष सभी तथ्य रखे थे। निष्पक्ष जांच में सच्चाई सामने आ गई और मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।कहा कि वे बीएसए और जांच समिति का निष्पक्ष जांच के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

बंगला नंबर 4 पर अब प्रशासन का हुआ कब्जा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। मंडलायुक्त अयोध्या आवास के सामने रामपथ की दूसरी पटरी पर स्थित नगर निगम के बंगला नंबर चार पर आज प्रशासन ने ताला तोड़कर कब्जा ले लिया। यह बंगला बीते 17 जुलाई को आदित्य विक्रम अग्रवाल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नाम एलाट कर दिया गया है।मालूम हो कि मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में बंगला नंबर चार पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान के नाम पर संपादक शीतला सिंह (स्व.) को आवंटित किया गया था। बाबू शीतला सिंह के निधन के बाद जिला प्रशासन ने उस बंगले को रिक्त मानते हुए उसे खाली करने का नोटिस दिया था। इधर पता चला है कि बंगला नंबर 4 पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान से खाली न कराया जाए इसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है। इधर आज सुबह ही प्रशासन ने उक्त बंगले पर लगा ताला तोड़कर उसमें मौजूद सारा सामान निकाल बाहर कर दिया और अपना ताला जड़ दिया है।

राष्ट्रभक्ति का संदेश लेकर भाजपा 10 से 14 अगस्त तक हर वार्ड में निकलेगी तिरंगा यात्रा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।भारतीय जनता पार्टी द्वारा 10 से 14 अगस्त तक आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा अभियान की तैयारियों को लेकर भाजपा महानगर कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला में अभियान की रूपरेखा, विभिन्न कार्यक्रमों एवं मंडलवार तिरंगा यात्राओं की जानकारी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दी गई।कार्यशाला में भाजपा महानगर प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा अभियान का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना को मजबूत करना तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीरों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान शहीदों की प्रतिमाओं एवं स्मृति स्थलों की साफ–सफाई और सजावट की जाएगी।स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों तथा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के स्वजन का सम्मान किया जाएगा। साथ ही घर–घर संपर्क कर लोगों से अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराने का आग्रह किया जाएगा।भाजपा महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर की मुख्य तिरंगा यात्रा 13 अगस्त को गांधी पार्क से शहीद स्मृति स्थल तक निकाली जाएगी। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर से लता चौक तक भी तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि मंडल स्तर पर भी तिरंगा यात्राओं का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 10 अगस्त को पूरा मंडल में ब्लॉक मुख्यालय से पुलिस चौकी तक तथा अयोध्या मंडल में छोटी देवकाली चौराहे से लता चौक तक यात्रा निकलेगी। 11 अगस्त को देवकाली मंडल में साहबगंज रामजानकी मंदिर से चौक तक और 12 अगस्त को करियप्पा मंडल में रिकाबगंज से नियावां तक तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही महानगर के सभी वार्डों में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। गरिमा मौर्या, सर्वज्ञ सिंह, विनय निषाद, विपिन सिंह बब्लू, को अभियान संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यशाला में महामंत्री शैलेन्द्र कोरी, परमानंद मिश्र, शिवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष तिलकराम मौर्य , शशिप्रताप सिंह, अरविंद सिंह, हरभजन गौड, बाल कष्ण वैश्य, मंत्री प्रदीप यादव, प्रवीण दुबे, रवि सिंह, स्वाती सिंह, शिवम शुक्ला, मीडिया प्रभारी अमित मिश्र, जेपी श्रीवास्तव, रवि सोनकर, हेमंत जायसवाल, कपिल देव वर्मा, मुकेश तिवारी, प्रतिमा शुक्ला, आकाश सोमवंशी, स्वप्निल श्रीवास्तव सहित मोर्चा, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस जनों ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया तहरीर

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मनोज शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन व प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के समक्ष प्रभु हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा थमा कर नचवाने की विरोध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने हेतु एक तहरीर दी है।उक्त आशय कीजानकारी देते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने बताया तहरीर में नगर कोतवाल से सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करने की मांग करते हुए कहा 6 जुलाई को लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में हमारे आराध्य प्रभु हनुमान जी को अपनी पार्टी का झंडा थमा कर जिस प्रकार से उन्हें नचाया गया इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और यह सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान है भाजपा की इस कृत से हम सब की आस्था को गहरा आघात पहुंचा।श्री पाठक ने बताया कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह के साथ पर पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह,पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा, पी सी सी सदस्य उग्रसेन मिश्रा,जिला उपाध्यक्ष राम अवध पासी, अशोक कुमार सिंह , महिला कांग्रेस की रेनू राय , डॉ विनोद गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह फास्टर आदि प्रमुख लोग शामिल रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।